English → Hindi

The Australia Institute
Research that matters.

सदस्यता लें दान करें

होम / मीडिया विज्ञप्तियाँ / जल्दबाजी में किया गया, गुप्त और खारिज करने वाला - गंदा सौदा जो हमारे लोकतंत्र को नीचा दिखाता है

एएपी इमेज/मिक त्सिकास

मीडिया विज्ञप्ति

जल्दबाजी में किया गया, गुप्त और उपेक्षापूर्ण - वह गंदा सौदा जो हमारे लोकतंत्र को नीचा दिखाता है

13 फ़रवरी, 2025

लोकतंत्र और जवाबदेही

कल रात संघीय लिबरल पार्टी ने घोषणा की कि उसने चुनावी कानूनों पर अल्बानीज़ लेबर सरकार के साथ समझौता कर लिया है - और, आज सुबह, संसद के दोनों सदनों से शीघ्रतापूर्वक पारित होने के बाद यह कानून बन गया।

ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट द्वारा विधेयक के विस्तृत विश्लेषण में कई खामियों की पहचान की गई है, जिनका प्रमुख पार्टियां फायदा उठा सकती हैं; नए प्रवेशकों और स्वतंत्र उम्मीदवारों के साथ अनुचित व्यवहार; तथा यह खतरा कि करदाताओं के नए वित्त पोषण के करोड़ों डॉलर भ्रामक विज्ञापन पर खर्च हो सकते हैं।

गठबंधन के साथ लेबर के समझौतों ने एक खराब विधेयक को और भी बदतर बना दिया है:

- $1,000 की प्रकटीकरण सीमा के बजाय, जो लॉबिस्टों और कॉर्पोरेट हितों से नकद-पहुँच भुगतान का खुलासा करती थी, सीमा को बढ़ाकर $5,000 कर दिया गया है। चूँकि अल्बानी सरकार आम तौर पर मंत्रियों तक विशेषाधिकार प्राप्त पहुँच के लिए $1,500 और $5,000 के बीच शुल्क लेती है , इसलिए ऐसा लगता है कि नई व्यवस्था के तहत नकद-पहुँच भुगतान को शामिल नहीं किया जाएगा। उच्च सीमा के तहत अपने नकद-पहुँच भुगतान का खुलासा करने के लिए लॉबिस्ट को बार-बार ग्राहक बनना होगा।
- दान की सीमा 50,000 डॉलर (20,000 डॉलर से बढ़ाकर) कर दी गई है, जिसका मतलब है कि करोड़पति अभी भी बहुत ज़्यादा वित्तीय शक्ति का इस्तेमाल कर सकेंगे। चूँकि प्रमुख पार्टियों की नौ शाखाएँ हैं, और वे हर तीन साल में प्रति दानकर्ता चार दान ले सकते हैं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति या कंपनी हर चुनाव चक्र में किसी प्रमुख पार्टी को 1.8 मिलियन डॉलर दे सकती है।
- शीर्ष निकायों के लिए प्रावधान का अर्थ है कि ऑस्ट्रेलिया की बिजनेस काउंसिल, ऑस्ट्रेलिया की मिनरल्स काउंसिल तथा निहित स्वार्थों के लिए अन्य लॉबी समूह प्रत्येक सदस्य संगठन से 250,000 डॉलर तक ले सकते हैं , जो वास्तविक ऑस्ट्रेलियाई मतदाताओं के लिए निर्धारित 50,000 डॉलर से पांच गुना अधिक है।

"चुनावी बदलावों को संसद से पारित करने की यह एक जल्दबाजी, गुप्त और उपेक्षापूर्ण प्रक्रिया रही है। कल रात, सीनेट से बिल पर बहस करने की उम्मीद थी, बिना यह देखे कि लेबर और लिबरल ने क्या संशोधन तैयार किए हैं। 40 वर्षों में चुनाव कानूनों में सबसे बड़े बदलावों को बहु-पक्षीय संसदीय जांच द्वारा उचित जांच का सामना करना चाहिए था," **ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट के लोकतंत्र और जवाबदेही कार्यक्रम के निदेशक बिल ब्राउन ने** कहा ।

“सौभाग्य से, ये कानून अगले चुनाव, यानी 2028 के आसपास, तक लागू नहीं होंगे। इसका मतलब है कि अगली संसद के पास पारदर्शिता की कमी, प्रमुख पार्टियों की खामियों और स्वतंत्र और नए प्रवेशकों के साथ अनुचित व्यवहार को संबोधित करने का अभी भी मौका है।

"जबकि सरकार ने बिजनेस काउंसिल और मिनरल्स काउंसिल जैसी शीर्ष लॉबियों को समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, चैरिटी क्षेत्र को केवल मंत्री से एक पत्र मिला जिसमें भविष्य में 'सद्भावना से जुड़ने' का वादा किया गया था। चैरिटी क्षेत्र में सैकड़ों हज़ार ऑस्ट्रेलियाई लोग काम करते हैं, लेकिन सरकारें इसे एक विचारहीन चीज़ की तरह मानती हैं। कॉरपोरेट हितों को खुली छूट देते हुए धर्मार्थ वकालत को दबाना केवल सामुदायिक आवाज़ों को कमज़ोर करेगा।"

शेयर करना

सामान्य पूछताछ

एमिली बर्ड
कार्यालय प्रबंधक

02 6130 0530

mail@australiainstitute.org.au

मीडिया पूछताछ

ग्लेन कॉनली
वरिष्ठ मीडिया सलाहकार

0457 974 636

glenn.connley@australiainstitute.org.au

आरएसएस फीड

मीडिया विज्ञप्ति

बेहतर ऑस्ट्रेलिया के लिए उच्च प्रभाव अनुसंधान प्रदान करने में हमारा सहयोग करें

सदस्यता लें

एबोनी बेनेट, द ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट, लेवल 1, 113 कैनबरा एवेन्यू, ग्रिफ़िथ ACT 2603 द्वारा अधिकृत।

ऑस्ट्रेलिया संस्थान पूरे ऑस्ट्रेलिया में पारंपरिक स्वामियों के पैतृक संबंधों और संरक्षकता को मान्यता देता है। हम आदिवासी और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर संस्कृतियों और अतीत और वर्तमान के बुजुर्गों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं।

©1994–2025 द ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट

हम विचार बदलते हैं।